बयालीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(24.03.2023 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/चैत्र, 1945(शक)

सीपीबी सं. 1 खंड XLII

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी को ऋण सुविधाओं के विस्तार के संबंध में श्री निखिल वर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन। 1

परिशिष्ट

याचिका समिति की 23.03.2023 को हुई 28वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुनील कुमार सिंह
9. श्री सुशील कुमार सिंह
10. श्री मनोज कुमार तिवारी
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री राजन बाबूराव विचारे
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2.	श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3.	श्री तेनज़िन ज्ञलसन	-	उप सचिव

याचिका समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी को ऋण सुविधाओं के विस्तार के संबंध में श्री निखिल वर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह बयालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 23 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में 42वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी को ऋण सुविधाओं के विस्तार के संबंध में श्री निखिल वर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन।

श्री निखिल वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी को ऋण सुविधाओं के विस्तार के लिए याचिका संबंधी समिति के समक्ष 28 जुलाई, 2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

2. अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है, जहां प्राकृतिक सुंदरता का विभिन्न अर्थों में बहुत महत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की आबादी 64 हजार है जिसमें 50 हजार (78%) की शहरी आबादी और 14 हजार (22%) की ग्रामीण आबादी शामिल है। जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 2,013 निवासियों का जनसंख्या घनत्व है। अभ्यावेदनकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि यह चिंता का विषय है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी लक्षद्वीप में न तो बड़े/मध्यम स्तर के उद्योग हैं और न ही कोई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। इसलिए, स्थानीय आबादी अपनी आजीविका के लिए केवल दो प्रमुख कार्यकलापों-बागवानी और मत्स्य पालन पर निर्भर है। तथापि, उपर्युक्त दोनों क्षेत्र असंगठित हैं, फिर भी स्थानीय आबादी के लिए आय का प्रमुख स्रोत साबित हुए हैं। नारियल और मत्स्य पालन के उत्पादन के साथ-साथ इसके मूल्य संवर्धन और विपणन के मुद्दे को वाणिज्यिक स्तर पर विकसित नहीं किया गया है जिसके

कारण किसानों/उद्यमियों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, प्रसंस्कृत मछली और अन्य संबंधित वस्तुओं जैसे मछली/झींगा का अचार, मछली प्रसंस्करण, मछली का मांस आदि के निर्यात की व्यापक गुंजाइश है, लेकिन विभिन्न नारियल आधारित उत्पादों जैसे - कॉयर कोवेलिंग फाइबर, कॉयर रस्सी, कॉयर यार्न, कॉयर मैट, नारियल तेल, सूखा नारियल, फाइबर ब्रश, नारियल शेल पाउडर, ऐक्टिवेटेड शेल कार्बन, प्रेस्ड स्पेशल बोर्ड, नारियल क्रीम, नारियल पानी की बोतलों में पिछले सात दशकों के दौरान कोई बड़ा विकास नहीं देखा गया है।

3. अभ्यावेदनकर्ता ने यह भी बताया है कि लक्षद्वीप में भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक नामक दो प्रमुख बैंक हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आज तक बागवानी और मतस्य पालन जैसे कार्यकलापों में शामिल स्थानीय आबादी को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यावहारिक नीतियां नहीं अपनाई हैं। इन बैंकों के नीति निर्माता ऐसी ऋण नीतियां तैयार करते हैं जो अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रभावी हो सकती हैं, तथापि, लक्षद्वीप के लिए ऋण नीतियों को स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि यदि बैंक संपार्श्विक सुरक्षा, गारंटर और अन्य प्रतिगामी और लंबे कागजी-कार्य/दिशानिर्देशों की आवश्यकता का सख्ती से पालन करके लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी को ऋण देने की ऋण नीति को लागू करते हैं, तो इस क्षेत्र में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी और पूरे द्वीप पर यथास्थिति बनी रहेगी और यह द्वीप कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा।

4. अभ्यावेदनकर्ता ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक को बागवानी और मत्स्य पालन संबंधी कार्यकालापों में शामिल स्थानीय आबादी को ऋण देने के लिए आवश्यकता-आधारित, यथार्थवादी और लीक से हटकर ऋण नीतिय तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्थानीय आबादी को 50 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मात्रा में ऋण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें छोटी मात्रा में अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता है, जिसे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आसानी से दिया जा सकता है।

5. याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निर्देश 95 के तहत श्री निखिल वर्मा के अभ्यावेदन पर विचार किया। तदनुसार, अभ्यावेदन को वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को उसमें उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां व्यक्त करने के लिए भेजा गया था।

6. इसके उत्तर में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/6/2022-बीओए-I, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से इस मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं हैं: –

> *"केनरा बैंक, जो लक्षद्वीप के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक हैं, ने अवगत कराया है कि बैंक ने लक्षद्वीप के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र स्तरीय अध्ययन किया है और इस द्वीप के विकास के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात मत्स्य पालन, समुद्री खरपतवार की खेती और टूना प्रसंस्करण की पहचान की है। बैंक ने उल्लिखित तीन क्षेत्रों को शुरू करने की संभावना के बारे में चर्चा करने के*

लिए कृषि उप-समिति की एक बैठक भी बुलाई थी और यह पाया कि इस द्वीप पर कृषि और अन्य कार्यकलापों को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौती सीमित भूजोत है। चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बैंक ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से लीड जिला प्रबंधक ने 7 बसे हुए द्वीपों का दौरा किया है और महिला आबादी के बीच जागरूकता पैदा की, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रेडिट लिंकेज वाले स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 8 से बढ़कर 107 हो गई है जिसका कुल एक्सपोजर 1.48 करोड़ रुपये का है।

केनरा बैंक ने यह भी अवगत कराया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर ट्रायल बेसिस पर समुद्री खरपतवार की खेती की थी। केनरा बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण, कच्चे नारियल का तेल बनाने, ट्रूना फिश का अचार बनाने के कार्यकलापों के तहत कई कार्यकलापों को वित्तपोषित किया है। आय सृजन कार्यकलापों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1000 से अधिक मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

केनरा बैंक ने यह भी कहा है कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरूआत पर बैंक कृषि-अवसंरचना निधि के तहत भंडारण अवसंरचना, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज यूनिटों आदि के विकास के लिए वित्त पोषण कर सकता है। नारियल और इसके उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए वित्त को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना के तहत भी कवर किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अलावा, केनरा बैंक ने बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस द्वीप पर एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को प्रायोजित किया है।

इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अवगत कराया है कि एसबीआई ने लोगों की विभिन्न ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आबादी को ऋण की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण करेगी जहां मत्स्य पालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां, कॉयर और कॉयर से संबंधित अन्य विनिर्माण, नारियल व्यवसाय और इसी तरह की अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रित हैं। एसबीआई ने यह भी बताया है कि सर्वेक्षण के आधार पर समिति लक्षद्वीप और उसके आसपास विभिन्न अभियानों के माध्यम से द्वीप के समग्र विकास की योजना बनाएगी ताकि बैंक क्रेडिट सुविधाओं और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।"

7. श्री निखिल वर्मा के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए, समिति ने 12 सितंबर, 2022 को अगाती का तत्स्थानिक ऑन-द-स्पॉट अध्ययन दौरा किया। उक्त अध्ययन यात्रा के दौरान समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

8. लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी के लिए बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक लिखित उत्तर में बताया कि: –

केनरा बैंक

लक्षद्वीप में 3 बैंक 12 शाखाएं और 22 एटीएम/कैश रिसाइकलर के साथ काम कर रहे हैं। केनरा बैंक की 9 शाखाएं हैं, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की दो शाखाएं और यूको बैंक की एक शाखा है। संघ राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

31 मार्च 2021 को बैंकों की जमा राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। सी.डी अनुपात मार्च 2021 में 8% की तुलना में 31 मार्च 2022 को 9.50% था। केनरा बैंक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और द्वीप में अग्रणी बैंक का संयोजक बैंक है। केनरा बैंक ने भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत डिजिटल बैंकिंग इकाई खोली है। सभी बसे हुए गाँव बैंकिंग सुविधाओं से आच्छादित हैं। बित्रा को छोड़कर सभी बने हुए दीपों में ब्रिक्स और मोर्टार बैंक शाखाएं हैं। बित्रा लीड बैंक (केनरा बैंक) में एक एटीएम और बीसी है। आईपीपीबी बित्रा द्वीप में कार्य कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हैं। सीबीएस सभी शाखाओं में लागू किया गया है। लक्षद्वीप में संचालित शाखाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

शाखाओं का विवरण	स्थापना का वर्ष	कुल व्यवसाय (करोड़ में)	कुल कर्मचारी
केनरा बैंक			
विशेषीकृत एसएमई शाखा, कावारत्ती	5-फरवरी-1971	483.82	12
मिनीकॉय	21-अप्रैल-1971	99.18	6

एंड्रॉय	16-जुलाई-1972	121.28	8
अमेनि	12-अगस्त-1972	96.90	8
अगात्ती	3-दिसम्बर-1976	69.41	6
कल्पनि	3-दिसम्बर -1988	95.06	4
किल्टन	15-नवम्बर-1989	48.58	5
कदमत	6-दिसम्बर -1989	64.33	6
चेतलाट द्वीप	1-जनवरी-1996	35.20	5

भारतीय स्टेट बैंक			
कावारत्ती	2005	164.09	6
मिनीकॉय	2009	42.12	5

भारतीय स्टेट बैंक

कृषि पृष्टभूमि

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 वर्ग किमी (3220 हेक्टेयर) है और द्वीपों का सकल बुवाई क्षेत्र 2675 हेक्टेयर है। लगभग 641 हेक्टेयर में एक से अधिक बार बोयाई की जाती है, जो फसल क्षमता का 130 प्रतिशत बनता है। कृषि इस संघ शासित प्रदेश की 90% से अधिक आबादी के लिए आजीविका है, नारियल की खेती यहाँ की जनता की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है। नारियल की खेती लगभग 2600 हेक्टेयर में होती है। लगभग 7,80,000 नारियल के पेड़ है और नारियल का वार्षिक उत्पादन 69.89 (अनुमानित) मिलियन नारियल है। द्वीप समूह में सदियों से नारियल उगाया जाता रहा है। जोत का तेजी से उपखंड और विभाजन होने के कारण, किसान बहुत करीब से रोपण करते हैं और अपने खेतों को चिह्नित

करने के लिए सीमाओं या कोनों पर अधिक पौधे लगाते हैं, अतः सभी द्वीपों में अधिक संख्या में पेड़ पाये जाते हैं।

कृषि गतिविधियों में चुनौतियां

सीमित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण और मुख्य भू-भाग से दूर स्थित होने से लक्षद्वीप द्वीप समूह को कृषि और इससे संबन्धित सभी सामग्रियों के लिए मुख्य भू-भाग पर निर्भर रहना पड़ता है जो इसे महंगा बनाता है। अस्थिर परिवहन सुविधा एक बड़ी बाधा है। द्वीप की अजीबोगरीब प्रकृति किसी भी बड़े निवेश के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करती है। उधार लेने के लिए लोगों की सामान्य अनिच्छा भी ऋण वितरण को प्रभावित करती है।

कृषि ऋण सुविधाएं

केनरा बैंक 9 शाखाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाला अग्रणी बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक की लक्षद्वीप (कावारत्ती और मिनिकॉय) केंद्र शासित प्रदेश में 2 शाखाएं है। दिनांक 27.08.2022 तक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हमारे बैंक का कुल कृषि ऋण एक्सपोजर 5.30 करोड़ रुपये है। जिसमें से 90% कृषि स्वर्ण ऋण के अंतर्गत है और 10% मत्स्यन गतिविधियों के लिए मुद्रा संबद्ध कृषि ऋण के तहत है।

हमारे बैंक की निम्नलिखित योजनाएं हैं जिन्हें पात्रता मानदंडों के अनुसार लक्षद्वीप की जनता तक को प्रदान किया जा सकता है।

- **पीएमएफएमई)फॉर्मलज़ैशन ऑफ पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज(:** सभी नारियल किसानों और महिला एसएचजी का एक सहकारी मॉडल बनाया जाएगा ताकि पीएमएफएमई योजना के तहत निधियों का लाभ उठाकर और संबंधित विभागों ,बैंकिंग क्षेत्र और

केंद्रीय संगठनों के साथ उचित प्रशिक्षण और उचित लिंकेज के साथ नारियल और नारियल उप-उत्पादों का ठीक से विपणन किया जा सके। हमारा वर्तमान एक्सपोजर शून्य है। (योजना दिशानिर्देश संलग्न(

- **एआईएफ)कृषि अवसंरचना निधि योजना(** :लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ एआईएफ के तहत सहायता प्राप्त करके द्वीपों में आवश्यक भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है जहां बैंक योजना दिशानिर्देशों और पात्रता के आधार पर ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हमारा वर्तमान एक्सपोजर शून्य है।) योजना दिशानिर्देश संलग्न(
- **एफपीओ)किसान उत्पादक संगठन** :(केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का कृषि विभाग नारियल विकास बोर्ड ,एर्णाकुलम के सहयोग से नारियल क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए पहल कर सकता है जहां बैंक उधार दे सकते हैं। हमारा वर्तमान एक्सपोजर शून्य है।)योजना दिशानिर्देश संलग्न(

- ***पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना)*** : लक्षद्वीप के आसपास का समुद्र मत्स्य संसाधनों में समृद्ध है और मुख्य मत्स्य संसाधन टूना हैं। बैंक द्वीप समूह में पीएमएमवाई के तहत मत्स्यन गतिविधियों के लिए ऋण दे सकते हैं। हमारा वर्तमान एक्सपोजर 0.52 करोड़ रुपये है। (योजना दिशानिर्देश संलग्न)

- **केसीसी मत्स्यन:** मरीन मत्स्यन के तहत कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को केसीसी (एएच एंड एफ) योजना के तहत वित्तपोषित किया जा सकता है। हमारा वर्तमान एक्सपोजर शून्य है। (योजना दिशा-निर्देश संलग्न)

- **एसएचजी वित्तपोषण:** पर्याप्त विपणन सहायता के साथ एसएचजी समूहों द्वारा समुद्री शैवाल की खेती को उचित प्रशिक्षण के साथ क्रेडिट लिंकेज के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि पर्याप्त विपणन लिंकेज उपलब्ध हों तो अचार बनाने आदि जैसे मत्स्य उप-उत्पादन संबंधी लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारा वर्तमान एक्सपोजर शून्य है। (योजना दिशा-निर्देश संलग्न)

9. इसके बाद समिति ने विशेष रूप से लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी के लिए बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ केनरा बैंक/भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए किसी विशिष्ट सर्वेक्षण के साथ-साथ सरकार की विभिन्न वित्त संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता का पता लगाने के लिए द्वीप की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पूछताछ की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने निम्नवत बताया:–

<u>केनरा बैंक</u>

केन्द्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में केनरा बैंक ने लक्षद्वीप द्वीप के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र स्तरीय अध्ययन किया है और द्वीप के विकास के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है अर्थात (i) मत्स्यन , (ii) समुद्री खरपतवार की खेती और (iii) ट्टना प्रसंस्करण।

केन्द्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजक होने के नाते, हमने उपर्युक्त तीन गतिविधियों की संभावना के बारे में चर्चा करने के लिए कृषि उप-समिति की एक बैठक बुलाई थी।

हमने पाया कि लक्षद्वीप द्वीप में कृषि और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौती सीमित भूमि जोत है और एक समाधान के रूप में हमने द्वीप में ऋण देने की स्वयं सहायता समूह पद्धति को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 31.03.2021 तक क्रेडिट सहबद्धता वाले एसएचजी की कुल संख्या केवल 8 थी। हमने एसएचजी क्रेडिट सहबद्धता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से, लीड डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक ने 7 बसे हुए द्वीपों का दौरा किया एवं महिला आबादी के बीच जागरूकता पैदा की है। नतीजतन, 99 एसएचजी को केनरा बैंक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1.48 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है। द्वीप के सभी पात्र स्वयं सहायता समूह क्रेडिट से जुड़े हुए हैं। द्वीप-वार एसएचजी क्रेडिट सहबद्धता विवरण निम्नानुसार है;

केनरा बैंक द्वारा लिंक्ड एसएचजी क्रेडिट - वित्तीय वर्ष 2021-22		
शाखाएँ	**खातों की संख्या**	**राशि लाखों में**
अगाती	13	19.72
अमीनी	33	65.05
एंड्रोट	5	3.88
कदमत	10	10.74
कावारत्ती	7	17.12
मिनीकॉय	31	31.02
कुल	**99**	**148**

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने लक्षद्वीप द्वीप के कुछ स्थानों में समुद्री शैवाल की खेती प्रोयोगिक आधार पर की थी। पूर्णतया स्वच्छ पानी (क्रिस्टल

क्लियर वाटर) और लैगून समुद्री शैवाल की खेती के लिए बहुत अनुकूल हैं। हम प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, यद्यपि समुद्री शैवाल की खेती के लिए निवेश की आवश्यकताएं तुलनात्मक रूप से कम हैं ; केनरा बैंक एसएचजी मॉडल के तहत समुद्री शैवाल की खेती गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए तैयार है।

हमारे बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण, नारियल तेल बनाने, टूना अचार बनाने की गतिविधियों के तहत कई गतिविधियों को वित्तपोषित किया है।

भारतीय स्टेट बैंक

कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि, हमने सरकारी निकायों के साथ मिलकर ऋण क्षमता का आकलन करने और बैंक की विभिन्न ऋण सुविधाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं।

आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम
19.09.2021	मिनिकॉय	एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
21.05.2021	मिनिकॉय	सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेडीवाई, मुद्रा ऋण, एपीवाई के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
10.07.2022	कावारत्ती	कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक की

		उपस्थिति में समुद्री शैवाल किसानों और नारियल किसानों के लिए कृषि ऋण के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
10.03.2022	*कावारत्ती*	*मत्स्य पालन/कृषि के विशेष सचिव की उपस्थिति में मछुआरों के लिए कृषि वित्त के लिए जागरूकता कार्यक्रम।*
20.03.2022	*कवरत्ती*	*मत्स्य पालन के सहायक निदेशक के साथ एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।*

इसके अलावा, एंड्रोथ में एक नई शाखा खोलने के हमारे प्रस्ताव के दौरान हमने अप्रैल के महीने में क्षेत्र की क्षमताओं के आकलन के लिए एक अध्ययन किया है।

10. समिति ने लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन और लक्षद्वीप में केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संस्वीकृत और संवितरित कुल ऋणों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:–

(रू. करोड़ में)

	2019-20		*2020-21*		*2021-22*	
	संस्वीकृत	**संवितरित**	**संस्वीकृत**	**संवितरित**	**संस्वीकृत**	**संवितरित**

केनरा बैंक						
कृषि	*3.38*	*3.37*	*4.10*	*4.10*	*6.63*	*6.33*
एमएसएमई	*9.57*	*9.38*	*13.74*	*13.48*	*19.50*	*19.17*
आवास	*2.41*	*2.01*	*4.06*	*3.34*	*5.38*	*4.42*
शिक्षा	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.03*	*0.03*
अन्य	*1.56*	*1.56*	*2.76*	*2.76*	*17.34*	*17.22*
भारतीय स्टेट बैंक						
कृषि	*2.23*	*2.12*	*1.46*	*1.38*	*4.41*	*4.14*
एमएसएमई	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
आवास	*0.39*	*0.39*	*0.31*	*0.29*	*0.00*	*0.00*
शिक्षा	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
अन्य	*6.59*	*6.16*	*6.13*	*5.84*	*8.20*	*7.63*

11. इसके बाद समिति ने केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संस्वीकृत और संवितरित ऋणों की मात्रा के साथ-साथ इस क्षेत्र में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए पर्याप्त और स्पष्ट वित्तीय प्रोत्साहन और क्षेत्र को आत्मनिर्भर और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र में बदलने में बैंकों द्वारा ऋणों की संस्वीकृत करने/संवितरण करने की भूमिका के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:–

<u>केनरा बैंक</u>

बैंक के पास व्यक्तियों की सभी प्रमुख जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न ऋण उत्पाद हैं। विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए बैंक नीति और योजना दिशानिर्देश इस तरह से तैयार किए गए हैं कि यह ग्राहकों की

जरूरतों को पूरा करके क्षेत्र को आत्मनिर्भर और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रूप में बदलने के दीर्घकालिक उद्देश्य को पूरा करें ।

इसके अलावा, बैंक का मुख्य ध्यान ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित स्वयं सहायता समूहों/जेएलजी के माध्यम से व्यक्तियों के समूहों को कोई आय सृजन गतिविधि करने के लिए ऋण प्रदान करना है, जो बेहतर आजीविका और भेद्यता को कम करने में मदद करता है।

<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

भारतीय स्टेट बैंक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में ऋण देने की गतिविधियों में सबसे आगे रहा है। लोग मुख्य रूप से कृषि और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 3 वर्षों में कावारत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में 7.64 करोड़ रुपये की राशि के ऋण वितरित किए हैं।

12. लक्षद्वीप में अशोध्य ऋणों की स्थिति के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की: -

<u>केनरा बैंक</u>

लक्षद्वीप द्वीप में केनरा बैंक का कुल एनपीए 57.60 लाख रुपये है, जिसमें से एमएसएमई वित्त के तहत 43.32 लाख रुपये हैं।

<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

लक्षद्वीप द्वीप में भारतीय स्टेट बैंक का कुल एनपीए 14.00 लाख रुपये है।

13. समिति द्वारा लक्षद्वीप के आम आदमी के समक्ष आ रही समस्याओं/कठिनाइयों, जिसमें बैंकों द्वारा ऋण की संस्वीकृति और संवितरण से पहले ऋण चाहने वाले द्वारा पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं के साथ-साथ केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लक्षद्वीप में ऋण चाहने वालों से मांगी गई औपचारिकताओं की संख्या की तुलना में देश के अन्य भागों में स्थित ऋण चाहने वालों से मांगी गई औपचारिकताएं शामिल है, के बारे में स्पष्ट रूप से पूछे जाने पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने एक लिखित उत्तर में बताया:–

<u>केनरा बैंक</u>

उधारकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताएं नीचे दी गई हैं: –

(i) बैंक प्रारूप के अनुसार आवेदन।
(ii) केवाईसी दस्तावेज और तस्वीरें, आदि।
(iii) आय प्रमाण जैसे, वेतन पर्ची / आईटीआर / वित्तीय विवरण / बैंक विवरण (खुदरा ऋण)
(iv) ईसी और भूमि अभिलेख प्रति (कृषि ऋण)
(v) यूआरसी प्रति (एमएसएमई ऋण के लिए)
(vi) चालान / कोटेशन (परिसंपत्ति खरीद के लिए)
(vii) प्रवेश प्रस्ताव पत्र (शिक्षा ऋण के लिए)
(viii) संपत्ति / सुरक्षा दस्तावेज

(ix) परियोजना रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट

उपरोक्त औपचारिकताएं पूरे देश में लागू हैं और लक्षद्वीप के लिए अलग से कोई औपचारिकता नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋण संस्वीकृत करने के लिए पूरे देश में प्रचलित औपचारिकताओं का समान स्तर लक्षद्वीप में भी प्रचलन में है। यद्यपि, द्वीप के कुछ भागों में जहां लोग रह रहे हैं, भूमि का स्वामित्व सरकार (पंडाराम भूमि) के पास है और इसलिए हम ऐसे क्षेत्र के लिए बंधक सृजित करने में असमर्थ हैं और इसके लिए एक उपयुक्त विकल्प विकसित करने की आवश्यकता है।

14. समिति ने लक्षद्वीप में विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र/पुनर्वित्त/पशुपालन योजनाओं के विस्तार की भूमिका को समझने के लिए और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र में इन योजनाओं की सफलता में नए सिरे से समृद्धि लाने वाले आधारों के बारे में पूछताछ की कि केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सभी हितधारकों/विभागों/संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए क्या सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसके उत्तर में, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:–

केनरा बैंक

लक्षद्वीप के यूटीएलबीसी संयोजक और अग्रणी बैंक होने के नाते, केनरा बैंक लक्षद्वीप में कार्यरत सभी संबंधित विभागों और बैंकरों के साथ निरंतर संपर्क और अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। बैंक उपर्युक्त संस्थाओं में मासिक बैठकें आयोजित कर रहा है जहां सभी हितधारक/विभाग/संस्थाएं स्थानीय सरकार की योजनाओं को लागू करने के अलावा सभी सरकारी योजनाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मंच हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत केनरा बैंक का प्रदर्शन:

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप			
	कुल स्वीकृत खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	कुल संवितरित खातों की संख्या	संवितरित राशि
2022-23 (25.08.2022तक)	434	7	432	6
2021-22	691	16	691	16
2020-21	1505	21	1505	21

केसीसी योजना के तहत केनरा बैंक का प्रदर्शन:

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप			
	कुल स्वीकृत खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	कुल संवितरित खातों की संख्या	संवितरित राशि
2022-23 (30.06.2022 तक)	133	11	133	11

2021-22	571	4	571	4
2020-21	64	0.50	64	0.50

स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण योजना के तहत केनरा बैंक का प्रदर्शन:

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	*केन्द्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप*			
	कुल स्वीकृत खातों की संख्या	*स्वीकृत राशि*	*कुल संवितरित खातों की संख्या*	*संवितरित राशि*
2022-23 (30.06.2022तक)	*14*	*0.15*	*14*	*0.15*
2021-22	*94*	*1.52*	*94*	*1.52*

<u>भारतीय स्टेट बैंक</u>

हमारी राय के अनुसार, यूटीएलबीसी को सभी वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों को एक साथ लाने और द्वीपों के लिए उपयुक्त विशिष्ट क्रेडिट योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। विभिन्न ऋण योजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समुचित और लगातार निगरानी करने के लिए बैंकरों और विभागों की एक कोर टीम का गठन किया जाएगा।

15. लक्षद्वीप में 2675 हेक्टेयर में से लगभग 2600 हेक्टेयर में नारियल की खेती होने की सूचना रखने वाली समिति ने छोटे/सीमांत किसानों को ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने और लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में 'ऋण मेलों' का आयोजन करके बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए ऋण आउटरीच कार्यक्रम,

अर्थात 'ऋण मेलों' के आयोजन के बारे में पूछताछ की। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने निम्नलिखित जानकारी दी:-

<u>केनरा बैंक</u>

नारियल का संस्कृत पर्यायवाची शव्द "कल्पवृक्ष" है जिसका अर्थ है एक ऐसा पेड़ जो जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजनाओं की शुरूआत पर नारियल और उसके उत्पादों के वित्त पोषण के लिए पहले की पारंपरिक पद्धति की तुलना में वित्तपोषण के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया गया है। इन नई योजनाओं के अनुसार, बैंक कृषि अवसंरचना कोष के तहत भंडारण संरचना, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों आदि के विकास के लिए वित्त प्रदान कर सकता है। नारियल और उसके उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए वित को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के औपचारिकरण के तहत कवर किया जा सकता है। ये योजनाएं उच्च मूल्य के ऋण हैं जो लक्षद्वीप की प्रमुख फसल के वित्तपोषण के तरीके को प्रभावित करेंगे। केनरा बैंक उधारकर्ताओं द्वारा लागू किए गए सभी पात्र ऋणों को मंजूरी देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नियमित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, बैंक केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा कर रहा है जो लंबे समय में फल देगा। लक्षद्वीप द्वीप में कृषि और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौती सीमित भूमि जोत है और समाधान के रूप में केन्द्र शासित प्रदेस प्रशासन और यूटीएलबीसी द्वीप में ऋण देने की स्वयं सहायता समूह पद्धति को बढ़ावा दे रहा है। केनरा बैंक अब केंद्र शासित प्रदेश में वित्तपोषण के एसएचजी मॉडल के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऋण दे रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक

मिनिकॉय और कावारत्ती द्वीपों में नारियल की खेती उचित और वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा रही है और बल्कि यह ज्यादातर एक प्राकृतिक खेती है। इसलिए नारियल की वैज्ञानिक खेती शुरू करने और मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और तैयारी को लोकप्रिय बनाने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां अपनाई जा सकती हैं, ताकि बैंक कृषि ऋणों के साथ अचल परिसंपत्तियों के हिस्से के वित्तपोषण के लिए कदम उठा सकें।

टिप्पणियां/सिफारिशें

लक्षद्वीप में आर्थिक परिदृश्य

16. समिति ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों और उत्तरों के आलोक में श्री निखिल वर्मा के अभ्यावेदन की जांच करते हुए नोट किया कि भारत का सबसे छोटा संघ-राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीपसमूह है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ 36 द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप, 17 निर्जन द्वीप जुड़े टापू, चार नवगठित टापू और पांच जलमग्न चट्टानें शामिल हैं। बसे हुए द्वीप हैं कवरत्ती, अगाती, अमीनी, कड़मठ, किल्तान, चेतलात, बित्रा, एंड्रोट, कलपेनी और मिनिकॉय। लक्षद्वीप द्वीप समूह के सीमित भौगोलिक क्षेत्र और मुख्य भूमि से बहुत दूर स्थित होने के मद्देनजर, द्वीप अपने सभी कृषि आदानों और कच्चे माल के लिए मुख्य भूमि पर निर्भर करता है। समिति ने आगे नोट किया कि द्वीपों की विशिष्ट प्रकृति के साथ एक गैर-भरोसेमंद परिवहन और भंडारण सुविधा किसी भी प्रकार के निवेश के लिए मुख्य बाधाएं और सीमित विकल्प पैदा करती है। इसके अलावा, यह चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी लक्षद्वीप में न तो कोई बड़ा/मध्यम स्तर का उद्योग है और न ही कोई सरकारी क्षेत्र की इकाई है। इसलिए, स्थानीय आबादी अपनी आजीविका कमाने के लिए दो प्रमुख गतिविधियों अर्थात् बागवानी और मत्स्यन पर निर्भर है।

17. समिति को ज्ञात है कि उपर्युक्त दोनों क्षेत्र, हालांकि असंगठित क्षेत्र हैं लेकिन स्थानीय लोगों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत सिद्ध हुए हैं। समिति यह नोट कर चिंतित है कि नारियल की खेती की बागवानी गतिविधि के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि आज की तारीख में, नारियल और इसकी उपज का मूल्य संवर्धन और विपणन उन्नत और वाणिज्यिक स्तर तक विकसित नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय किसान/उद्यमी अपने उत्पादन के मूल्य के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इसके अलावा, मत्स्यन के संबंध में, समिति ने नोट किया कि बर्फ की समुचित व्यवस्था की कमी, भंडारण विकल्प की गैर-मौजूदगी, मछली पकड़ने के अप्रचलित उपकरण और ट्रॉलर के साथ-साथ मछली प्रसंस्करण के लिए उचित सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों के कारण पूरे मछली पकड़ने के उद्योग को बैकफुट पर ला दिया है।

18. समिति चाहती है कि सरकार उनके द्वारा बताए गए उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए। इसके लिए, समिति सरकार से सिफारिश करती है कि वे बागवानी और मात्स्यिकी संबंधी विभिन्न अवसंरचनात्मक बाधाओं से संबंधित मुद्दों जैसे बर्फ की नियमित और उचित व्यवस्था, मात्स्यिकी से संबंधित वस्तुओं के लिए पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ भंडारण विकल्पों का सृजन करने, उद्यमियों विशेष रूप से मछुआरों को रियायती दर पर मछली पकड़ने के उपकरण और ट्रॉलर प्रदान करने और समर्पित मछली प्रसंस्करण इकाइयों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए। समिति सरकार से द्वीपों के व्यापक विकास के लिए कुछ मध्यम/लघु स्तर के विशिष्ट उद्योगों की पहचान करने और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने का भी आग्रह करती है। ऐसे उद्योगों की प्रोफाइल स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और कृषि और समुद्री क्षमता के उपयोग से संबंधित कच्चे माल पर आधारित हो सकती है। इसके अलावा, विश्वसनीय विपणन संरचना के साथ-साथ एक स्थायी व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए एक रोडमैप का भी उपयोग किया जा सकता है ताकि ऐसे उद्योगों के उत्पादन के लिए उचित बाजार सुनिश्चित किया जा सके।

बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क में सुधार

19. समिति नोट करती है कि बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क के विस्तार से संबंधित मुद्दों के संबंध में, कुछ कमियां विद्यमान हैं जिन्हें आज की स्थिति के अनुसार समग्र जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप द्वीप समूह की प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द दूर किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह भी

नोट करने के लिए बाध्य है कि लक्षद्वीप में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप समूहों में नेटवर्क में सुधार करने के अपने प्रयास में आंशिक रूप से सफल रही है। समिति नोट करती है कि केनरा बैंक लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है और इसने द्वीपों के विकास से संबंधित संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक क्षेत्र स्तरीय अध्ययन किया है। समिति चाहती है कि केनरा बैंक यूटीएलबीसी संयोजक और लक्षद्वीप का अग्रणी बैंक होने के नाते लक्षद्वीप में कार्यरत सभी स्थानीय स्तर प्रमुख विभागों और बैंकरों के साथ निरंतर संपर्क सुनिश्चित करे और सभी संस्थाओं की नियमित बैठकें आयोजित करे, जहां सभी हितधारक और विभाग अपने बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क में सुधार सुनिश्चित करते हुए सभी सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक ही मंच पर हों।

20. समिति आग्रह करती है कि अग्रणी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बैठकें, विशेष रूप से यूटीएलबीसी की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं और यूटीएलबीसी बैठकों के संचालन के संबंध में मानक निर्देशों के अनुसार सभी कार्यसूची मदों पर विस्तार से चर्चा की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि बैंकों और स्थानीय प्रशासन को कृषि, पर्यटन और मात्स्यकी क्षेत्रों की क्षमता के बेहतर समुपयोग के माध्यम से नकद-जमा अनुपात में सुधार करने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। मूल्य श्रृंखला और द्वीप आबादी के प्रबंधन कौशल के साथ उद्यमशीलता की भावना और तकनीक में सुधार करते समय भी यही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान द्वीप की *प्रति व्यक्ति जनसंख्या* और बैंकिंग और वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लोगों के सीमित अंतर-द्वीप आवागमन को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न बैंकों की अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए, उपर्युक्त द्वीपों में नई शाखाएं अधिमानतः अन्य बैंकों (केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के अलावा) द्वारा खोली जा सकती हैं, जो द्वीप आबादी के लिए बैंकिंग सेवाओं की अधिक विविधता लाने

में मदद करेंगी और बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगी, जिससे अंततः ग्राहकों को लाभ होगा और बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क में सुधार होगा।

21. समिति आगे सिफारिश करती है कि लक्षद्वीप की समग्र जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और परामर्श अभियान के माध्यम से कवर नहीं किए गए परिवारों को बैंकिंग और क्रेडिट के दायरे में आने के लिए उन्हें समझाने और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित और ठोस प्रयास किए जाएं। इसके अलावा, बैंकिंग और वित्तीय शिक्षा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के साथ संबंध के लाभों और आर्थिक विकास और प्रगति के बारे में स्थानीय जनसंख्या को जागरूक करने में एक सार्थक भूमिका निभा सकती है। क्रेडिट परामर्श शिविरों के साथ वित्तीय साक्षरता और शिक्षा अभियानों के माध्यम से इसे और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए बैंकों द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से स्थानीय भाषाओं/बोलियों में पुस्तिकाएं लाई जा सकती हैं, सरकारी विभागों और जन प्रतिनिधियों के साथ सभी हितधारकों को शामिल करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। समिति यह भी चाहती है कि इस संबंध में प्राप्त परिणामी उपलब्धियों पर एक 'मूल्यांकन रिपोर्ट' उनके साथ साझा की जाए।

ऋण प्रावधान और वित्तीय समावेशन

22. समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बागवानी, मात्स्यिकी आदि जैसे कार्यकलापों में शामिल स्थानीय जनसंख्या को ऋण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में व्यावहारिक नीतियां नहीं अपनाई हैं। लक्षद्वीप के लिए ऋण नीतियों को स्थानीय आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने की आवश्यकता के बावजूद, बैंकों के नीति और निर्णयकर्ता ने 'सभी की जरुरत समान है' के दृष्टिकोण के साथ ऋण नीतियां तैयार की हैं। समिति आगे नोट करती है कि लक्षद्वीप के सीमित भौगोलिक क्षेत्र और मुख्य भूमि से बहुत दूर स्थित होने

के मद्देनजर, इसके सभी आदानों के लिए प्रमुख गतिविधियां इसे अपेक्षाकृत महंगी बनाती हैं। एक गैर-भरोसेमंद परिवहन सुविधा भी एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा, द्वीपों की असामान्य प्रकृति किसी भी बड़े निवेश के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करती है और सामान्य रूप से लोगों की उधार लेने की अनिच्छा ने भी ऋण के प्रवाह को प्रभावित किया है।

23. समिति नोट करती है कि केनरा बैंक लक्षद्वीप में कार्य करने वाला अग्रणी बैंक है जबकि भारतीय स्टेट बैंक की केवल दो शाखाएं हैं। केनरा बैंक ने समिति को बताया है कि उन्होंने लक्षद्वीप द्वीप समूह के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षेत्र स्तरीय अध्ययन किया है और द्वीप के विकास के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाया है। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों को ऋण के मुद्दे की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जबकि उक्त समिति विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण करेगी जहां मत्स्यन, कॉयर और नारियल से संबंधित विनिर्माण व्यावसायिक कार्यकलापों जैसी गतिविधियां केंद्रित हैं और जो अध्ययन पर आधारित हैं। समिति लक्षद्वीप में और उसके आसपास विभिन्न अभियानों के माध्यम से द्वीप के समग्र विकास के लिए भी योजना बनाएगी ताकि बैंक ऋण सुविधाओं और इसके उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

24. समिति ने नोट किया कि कृषि ऋण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में, अगस्त, 2022 तक केनरा बैंक का कुल कृषि ऋण एक्सपोजर 5.30 करोड़ रुपये है, जिसमें से 90% कृषि स्वर्ण ऋण के तहत और 10% मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए मुद्रा कृषि ऋण के तहत है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि बहुत सी योजनाएं, जैसे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई), कृषि अवसंरचना निधि योजना (एआईएफ), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूहों

(एसएचजी) वित्तपोषण आदि, एकतरफा हैं और कृषि ऋण के दायरे तक ही सीमित हैं। इसके अलावा, पीएमएफएमई, एआईएफ, एफपीओ, केसीसी मत्स्य पालन और एसएचजी वित्तपोषण जैसी अधिकांश योजनाओं में कोई एक्सपोजर नहीं है, जबकि पीएमएमवाई में केवल 52 लाख रुपये का एक्सपोजर है।

25. इसलिए, समिति विभिन्न ऋण नीतियों को उपलब्ध कराने के माध्यम से ऋण के एकतरफा फैलाव में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश करती है। इस संबंध में, बैंकों और सरकार की विभिन्न वित्त संबंधी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के साथ-साथ ऋण मांग में वृद्धि की संभावना की तुलना में जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए एक 'तथ्यान्वेषी समिति' के रूप में एक विशिष्ट सर्वेक्षण/विश्लेषण किया जा सकता है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि लक्षद्वीप के संबंध में स्थानीय जनसंख्या की विशिष्ट परिस्थितियों और भौगोलिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए ऋण नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए संपार्श्विक सुरक्षा, गारंटर और इस तरह के अन्य प्रतिगामी और लंबे कागजी कार्य/दिशानिर्देशों की दृढ़ आवश्यकता के अनुपालन से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और दृष्टिकोण में इस हद तक ढील देने की आवश्यकता है ताकि तंत्र को सुविधाजनक और सुचारू बनाया जा सके। इसके अलावा, ऋण की मात्रा के संबंध में आवश्यकता अपेक्षाकृत कम है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए समिति बैंकों और सरकार से संबंधित ऋण सुविधाओं और उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से लक्षद्वीप के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'तदनुरूप' और 'स्थानीय' वित्त और ऋण नीतियों की दृढ़ता से सिफारिश करती है। समिति इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)/पीएसबी द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली,

श्री हरीश द्विवेदी
सभापति,
याचिका समिति

23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)